बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 119 ● नई दिल्ली ● वीरवार 19 फरवरी 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

चांदी की कीमतों में 6600 रुपये का उछाल, सोना 1.53 लाख रुपये पर पहुंचा

नई दिल्ली । सोने-चांदी की कीमतों में बुधवार को तेजी देखने को मिली। बुलियन की दरों के अनुसार चांदी की कीमत 6630 रुपये बढ़कर 2.37 लाख रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। वहीं सोना 1000 रुपये की तेजी के साथ 1.53 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर अप्रैल डिलीवरी वाला सोना 1 प्रतिशत से ज्यादा उछलकर 1,53,554 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया, जो दिन का उच्चतम स्तर है। वहीं मार्च डिलीवरी वाली चांदी करीब 4 प्रतिशत की तेजी के साथ 2,38,564 रुपए प्रति किलोग्राम के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तीसरे सत्र में गिरावट दर्ज की गई। एशियाई बाजारों में लूनर न्यू ईयर की छुट्टियों के कारण कम कारोबार के बीच कीमती धातुओं पर दबाव बना रहा।

पहली बार नौकरी की तलाश में निकले युवाओं के लिए खुशखबरी, नियोक्ता दे सकते हैं फेशर्स को प्राथमिकता

नई दिल्ली । पहली बार नौकरी की तलाश में निकले युवाओं के लिए यह साल अच्छा साबित हो सकता है। 73 प्रतिशत नियोक्ता पहली छमाही में फ्रेशर्स को नौकरी पर रखने की योजना बना रहे हैं। टीमलीज एडटेक करियर की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार भर्ती संबंधी निर्णय मुख्य रूप से इंटर्नशिप और वास्तविक दुनिया के प्रोजेक्ट अनुभव से प्रेरित होते हैं, न कि केवल शैक्षणिक योग्ताओं से। इसमें कहा गया है कि लगभग 4 में से 3 नियोक्ता फ्रेशर्स को नियुक्त करने का इरादा रखते हैं।

यह पिछले छमाही की तुलना में तीन प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। यह डेटा नवंबर 2025 और जनवरी 2026 के बीच सर्वेक्षण किए गए 1,051 नियोक्ताओं से लिए गए इनपुट पर आधारित है।

किन क्षेत्रों में है सबसे ज्यादा मांग?

रिपोर्ट में आगे यह भी पता चला कि क्षेत्रीय मांग में खुदरा बाजार (91 प्रतिशत) सबसे आगे है।

उसके बाद ई-कॉमर्स और प्रौद्योगिकी स्टार्टअप (90 प्रतिशत) और विनिर्माण (85 प्रतिशत) का स्थान आता है।

रिटेल सेक्टर में सबसे अधिक मांग वाले पदों में डार्क स्टोर असिस्टेंट और इन्वेंटरी मैनेजमेंट असिस्टेंट शामिल हैं।

वहीं ई-कॉमर्स और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप डिजिटल सेल्स एसोसिएट और जूनियर वेब डेवलपर पदों के लिए भर्तियां कर रहे हैं।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि विनिर्माण क्षेत्र में इन्वेंटरी और लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेटर और बैटरी असेंबली टेक्नीशियन की भूमिकाओं की मांग सबसे अधिक है।

युवा प्रतिभाओं के कार्यबल में शामिल होने के तरीके में आया संरचनात्मक बदलाव

टीमलीज एडटेक के संस्थापक और सीईओ शांतनु रूज ने कहा कि हम देख रहे हैं कि युवा प्रतिभाओं के कार्यबल में शामिल होने के तरीके में एक संरचनात्मक बदलाव आ रहा है। इस छमाही में फ्रेशर्स को नौकरी देने की इच्छा 73 प्रतिशत तक बढ़ गई है, जो प्रवेश स्तर की प्रतिभाओं में नियोक्ताओं के सतर्क लेकिन स्पष्ट विश्वास को दर्शाती है। कुछ क्षेत्रों में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है - खुदरा क्षेत्र में भर्ती की इच्छा 50 प्रतिशत अंक बढ़कर 2025 की पहली छमाही में 41 प्रतिशत से 2026 की पहली छमाही में 91 प्रतिशत हो गई है।

पहुंच अधिक होती जा रही है चयनात्मक

उन्होंने कहा कि यात्रा क्षेत्र में 51 अंकों की वृद्धि हुई है, जो 26 प्रतिशत से बढ़कर 77 प्रतिशत हो गया है। बिजली और ऊर्जा क्षेत्र में 50 अंकों की वृद्धि हुई है, जो 22 प्रतिशत से बढ़कर 72 प्रतिशत हो गया है, जो युवा पेशेवरों की मांग में मजबूत उछाल का संकेत देता है। फिर भी, उन्होंने कहा कि अवसर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उन तक पहुंच अधिक चयनात्मक होती जा रही है।

असली अंतर किस आधार पर दिख रहा?

रूज ने आगे कहा कि आजकल असली अंतर उन उम्मीदवारों के बीच है जो व्यावहारिक कौशल प्रदर्शित कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते। इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो या व्यावहारिक अनुभव वाले फ्रेशर्स तेजी से विकास के अवसरों की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि केवल डिग्री धारक आवेदकों को नौकरी ढूंढने में लंबा समय लगता है। इसका समाधान सीखने की प्रक्रिया में कार्य-प्रदर्शन के प्रमाण को शामिल करने में निहित है।

बंगलूरू फ्रेशर्स हायरिंग के मामले में है सबसे आगे

इस बीच, रिपोर्ट में कहा गया है कि बंगलूरू भौगोलिक रूप से 84 प्रतिशत के साथ फ्रेशर्स की भर्ती के इरादे में सबसे आगे है।

मुंबई भी फ्रेशर्स हायरिंग के मामले में आगे

इसके बाद मुंबई का स्थान आता है, जहां इसकी मांग 72 प्रतिशत है, जो खुदरा (91 प्रतिशत), एफएमसी (80 प्रतिशत) और स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स (52 प्रतिशत) क्षेत्रों द्वारा संचालित है, जिसमें बीआईएम समन्वय सहायक (55 प्रतिशत), डिजिटल सेल्स एसोसिएट (58 प्रतिशत) और क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट (45 प्रतिशत) की मजबूत मांग है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि ये शहर मिलकर भारत में प्रवेश स्तर की भर्ती गतिविधियों के बहुमत के लिए जिम्मेदार हैं, जो फ्रेशर्स को प्रौद्योगिकी, संचालन, स्वास्थ्य सेवा और वाणिज्य क्षेत्रों में विविध अवसर प्रदान करते हैं।

आज आम जनता के लिए बंद रहेगा एक्सपो, आयोजकों ने बढ़ाई समिट की अवधि

नई दिल्ली । भारत सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 को जबरदस्त प्रतिक्रिया को देखते हुए एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले यह समिट 20 फरवरी को समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब यह 21 फरवरी तक चलेगी। सरकार के अनुसार, बड़ी संख्या में आए विजिटर्स और एग्जिबिटर्स को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है, ताकि सभी को समिट और प्रदर्शनी का बेहतर अनुभव मिल सके। इसके साथ ही एक्सपो के समय में भी बदलाव किया गया है। अब प्रदर्शनी का समय शाम 6 बजे के बजाय रात 8 बजे तक रहेगा, जिससे आगंतुकों को अधिक समय मिल सके। हालांकि, 19 फरवरी (गुरुवार) को प्रतिबंधित कार्यक्रमों के कारण समिट आम जनता के लिए बंद रहेगी। वहीं, प्रदर्शनी 20 और 21 फरवरी को आम लोगों के लिए खुली रहेगी। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इंसमिट के लिए अब तक तीन लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बढ़ते उत्साह को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि करीब 2.5 लाख लोग, जिनमें अधिकांश 30 वर्ष से कम उम्र के हैं, अब तक प्रदर्शनी क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं। समिट की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण को फिलहाल अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। वेबसाइट पर जारी सूचना में कहा गया है कि भारी प्रतिक्रिया और सीमित ऑन-साइट क्षमता के कारण समिट ओवरसब्सक्राइब्ड हो चुकी है, जिससे एआई को लेकर लोगों की बढ़ती रुचि साफ झलकती है। कार्यक्रम के पहले दिन हुई अव्यवस्थाओं को लेकर मंत्री वैष्णव ने प्रतिभागियों से खेद भी जताया। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े एआई आयोजनों में शामिल इस समिट में उम्मीद से ज्यादा भीड़ के कारण कुछ दिक्कतें सामने आईं। वैष्णव ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार फीडबैक के प्रति खुली सोच रखती है और प्रतिभागियों को बेहतर और सुगम अनुभव देने के लिए आवश्यक सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

वैश्विक एआई प्रतिस्पर्धा में भारत कहां? शीर्ष देशों पर ये बोले इंफोसिस के सह-संस्थापक

नई दिल्ली ।

भारत वैश्विक एआई प्रतिस्पर्धा में शीर्ष तीन देशों में स्थान बना सकता है। इंफोसिस के सह-संस्थापक क्रिस गोपालकृष्णन ने यह बात कही। उनके अनुसार भारत में मजबूत डेवलपर इकोसिस्टम और अनुप्रयोगों पर बढ़ते फोकस के चलते देश के पास यहां तक पहुंचने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि एआई की असली ताकत सिर्फ तकनीक होने में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि उससे कौन-कौन से काम के एप्लिकेशन बनाए और इस्तेमाल किए जाते हैं। भारत एक विशाल देश है जिसमें बड़ी संख्या में एप्लिकेशन और डेवलपर्स हैं। उनके अनुसार, भारत में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनने की क्षमता है, विशेष रूप से एप्लिकेशन स्तर पर, जहां वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए एआई समाधानों का उपयोग किया जाता है। उन्होंने भारत में उन्नत एआई प्रणालियों, जिनमें बहु-मॉडल और बहुभाषी मॉडल शामिल हैं, के विकास के लिए चल रहे प्रयासों की ओर भी इशारा किया। ये मॉडल केवल अंग्रेजी आधारित मॉडलों से काफी अलग हैं और इन्हें विभिन्न भाषाओं और उपयोग के मामलों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो भारत की भाषाई विविधता और तकनीकी महत्वाकांक्षा को दर्शाते हैं। गोपालकृष्णन ने विशेष रूप से कम बिजली खपत वाली कंप्यूटिंग के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार में निवेश के महत्व पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि कम बिजली खपत वाली कंप्यूटिंग में प्रगति अगली पीढ़ी के प्रोसेसर को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जो भविष्य में एआई विकास को गति प्रदान करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में एआई पर चर्चा और शिखर सम्मेलन आयोजित करने से वैश्विक एआई पारिस्थितिकी तंत्र में देश की स्थिति मजबूत होगी। भारत में एआई पर वैश्विक चर्चाओं को लाने से भविष्य की प्रौद्योगिकियों की दिशा तय करने और नए अवसरों को खोलने में मदद मिलेगी।

एआई के व्यावहारिक उपयोगों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है भारत : अश्विनी वैष्णव

नई दिल्ली । सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि भारत, कृत्रिम मेधा (एआई) के व्यावहारिक उपयोगों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जिसमें उद्यमों की उत्पादकता बढ़ाना तथा स्वास्थ्य, कृषि एवं जलवायु परिवर्तन जैसी जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों के समाधान शामिल हैं। राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के तहत एक शोध संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मंत्री ने एआई प्रदर्शनी में मंगलवार को युवाओं की मजबूत भागीदारी और उनमें दिखे उत्साह को लेकर खुशी जाहिर की। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी में करीब ढाई लाख लोगों ने हिस्सा लिया जिनमें अधिकतर की उम्र 30 वर्ष से कम थी। वैष्णव ने कहा, जब मैंने युवाओं से बात की तो जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। मैं इस बात से हैरान था कि अधिकतर युवाओं ने अपने लिए आ रहे इस अवसर को लेकर कितना सकारात्मक नजरिया अपनाया है। मंत्री ने कहा कि उन्हें भारत और दुनिया के लिए एक बिल्कुल नए भविष्य की उम्मीद दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा, +भारत में हम सीमांत स्तर पर कृत्रिम मेधा, व्यावहारिक उपयोगों के लिए एआई, वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए एआई, उद्यमों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए एआई और स्वास्थ्य, कृषि एवं जलवायु परिवर्तन जैसी जनसंख्या से जुड़ी समस्याओं पर खास ध्यान दे रहे हैं। भारत में यही हमारी प्राथमिकता है और यह सम्मेलन ऐसे ही अवसर प्रदान करता है। मंत्री ने संगोष्ठी में शामिल प्रतिभागियों से कृत्रिम मेधा को सुरक्षित बनाने के लिए ठोस एवं व्यावहारिक सुझाव देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कृत्रिम मेधा एक सशक्त उपकरण है और इसका उपयोग मानवता के हित में होना चाहिए। देश के सबसे बड़े वैश्विक कृत्रिम मेधा सम्मेलनों में शामिल इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में नीति निर्माता, उद्योग जगत के लोग और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ एकत्र हुए हैं तथा यहां नवाचार, संचालन व्यवस्था एवं वास्तविक उपयोगों पर विचार-विमर्श जारी है।

गूगल प्रमुख सुंदर पिचाई ने पीएम मोदी से की मुलाकात, एआई इम्पैक्ट समिट में 20 फरवरी को लेंगे भाग

नई दिल्ली । गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने राजधानी दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। पिचाई भारत में आयोजित ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में हिस्सा लेने आए हैं और 20 फरवरी को समिट में मुख्य भाषण देंगे। भारत पहुंचने पर पिचाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि एआई इम्पैक्ट समिट के लिए भारत लौटकर खुशी हो रही है और यहां हमेशा की तरह गर्मजोशी से स्वागत किया गया। भारत पहुंचने पर पिचाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि एआई इम्पैक्ट समिट के लिए भारत लौटकर खुशी हो रही है और यहां हमेशा की तरह गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन 16 से 20 फरवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जा रहा है। इस

वैश्विक समिट में दुनियाभर के नीति निर्माता, एआई विशेषज्ञ, शिक्षाविद, टेक इनोवेटर और सिविल सोसायटी के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े वैश्विक मुद्दों, शासन, सुरक्षा और सामाजिक प्रभाव पर चर्चा की जा रही है।

एआई फॉर ह्यूमैनिटी

यह समिट ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला पहला बड़ा वैश्विक एआई सम्मेलन माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य एआई फॉर ह्यूमैनिटी के सिद्धांत के साथ एआई की परिवर्तनकारी क्षमता पर विचार करना है। समिट में 110 से अधिक देशों, 30 अंतरराष्ट्रीय संगठनों, करीब 20 राष्ट्राध्यक्ष/सरकार प्रमुख स्तर के प्रतिनिधि और लगभग 45 मंत्रियों की भागीदारी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई के बढ़ते प्रभाव पर कहा कि भारत का आईटी सेक्टर सेवाओं के निर्यात और आर्थिक विकास की रीढ़ रहा है और एआई इस क्षेत्र के लिए बड़ा अवसर और चुनौती दोनों है। उन्होंने कहा कि एआई आधारित आउटसोर्सिंग और ऑटोमेशन के चलते 2030 तक भारत का आईटी सेक्टर 400 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। समिट तीन प्रमुख स्तंभों पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस पर आधारित है, जिनका उद्देश्य मानव-केंद्रित, टिकाऊ और समावेशी एआई विकास को बढ़ावा देना है, ताकि तकनीक का लाभ समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से पहुंच सके।

वीर शिवाजी

भारत के वीर सपूतों में से एक श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सभी लोग जानते हैं। कुछ लोग इन्हें मराठा गौरव कहते हैं, जबकि वे भारतीय गणराज्य के महानायक थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म सन् 19 फरवरी 1630 में मराठा परिवार में हुआ। कुछ लोग 1627 में उनका जन्म बताते हैं। उनका पूरा नाम शिवाजी भोंसले था। शिवाजी के पिता शाहजी थे और माता जीजाबाई थे के पुत्र थे। उनका जन्म पुणे के पास स्थित शिवनेरी का दुर्ग में हुआ था। राष्ट्र को विदेशी और आततायी राज्य-सत्ता से स्वाधीन करा सारे भारत में एक सार्वभौम स्वतंत्र शासन स्थापित करने का एक प्रयत्न स्वतंत्रता के अनन्य पुजारी वीर प्रवर शिवाजी महाराज ने भी किया था। इसी प्रकार उन्हें एक अग्रगण्य वीर एवं अमर स्वतंत्रता सेनानी स्वीकार किया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का विवाह सन् 14 मई 1640 में सइबाई निम्बालकर के साथ लाल महल, पूना में हुआ था। उनके पुत्र का नाम सम्भाजी था। सम्भाजी शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी थे, जिसने 1680 से 1689 ई. तक राज्य किया। शम्भा जी में अपने पिता की कर्मठता और दृढ़ संकल्प का अभाव था। सम्भाजी की पत्नी का नाम येसुबाई था। उनके पुत्र और उत्तराधिकारी राजाराम थे। शिवाजी के बढ़ते प्रताप से आतंकित बीजापुर के शासक आदिलशाह जब शिवाजी को बंदी नहीं बना सके तो उन्होंने शिवाजी के पिता शाहजी को गिरफ्तार किया। पता चलने पर शिवाजी आगबबूला हो गए। उन्होंने नीति और साहस का सहारा लेकर छापामारी कर जल्द ही अपने पिता को इस कैद से आजाद कराया। तब बीजापुर के शासक ने शिवाजी को जीवित अथवा मुर्दा पकड़ लाने का आदेश देकर अपने मक्कार सेनापति अफजल खां को भेजा। उसने भाईचारे व सुलह का झूठा नाटक रचकर शिवाजी को अपनी बांहों के घेरे में लेकर मारना चाहा, पर समझदार शिवाजी के हाथ में छिपे बघनखे का शिकार होकर वह स्वयं मारा गया। इससे उसकी सेनाएं अपने सेनापति को मरा पाकर वहां से दुम दबाकर भाग गईं।शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित हो कर मुगल बादशाह औरंगजेब ने दक्षिण में नियुक्त अपने सूबेदार को उन पर चढ़ाई करने का आदेश दिया। लेकिन सुबेदार को मुंह की खानी पड़ी। शिवाजी से लड़ाई के दौरान उसने अपना पुत्र खो दिया और खुद उसकी अंगुलियां कट गईं। उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। इस घटना के बाद औरंगजेब ने अपने सबसे प्रभावशाली सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह के नेतृत्व में लगभग 1,00,000 सैनिकों की फौज भेजी। शिवाजी को कुचलने के लिए राजा जयसिंह ने बीजापुर के सुल्तान से संधि कर पुरन्दर के क़िले को अधिकार में करने की अपने योजना के प्रथम चरण में 24 अप्रैल, 1665 ई. को व्रजगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। पुरन्दर के किले की रक्षा करते हुए शिवाजी का अत्यन्त वीर सेनानायक मुरार जी बाजी मारा गया। पुरन्दर के क़िले को बचा पाने में अपने को असमर्थ जानकर शिवाजी ने महाराजा जयसिंह से संधि की पेशकश की। दोनों नेता संधि की शर्तों पर सहमत हो गए और 22 जून, 1665 ई. को पुरन्दर की सन्धि सम्पन्न हुई।और फिर दक्षिण की ओर नासिक एवं पूना जिलों के बीच से होती हुई एक अनिश्चित सीमा रेखा के साथ समस्त सतारा और कोल्हापुर के जिले के अधिकांश भाग को अपने में समेट लेती थी। 1. पूना से लेकर सल्हर तक का क्षेत्र कोंकण का क्षेत्र, जिसमें उत्तरी कोंकण भी सम्मिलित था, पेशवा मोरोपंत पिंगले के नियंत्रण में था।2. उत्तरी कनारा तक दक्षिणी कोंकण का क्षेत्र अन्नाजी दत्तो के अधीन था। 3. दक्षिणी देश के जिले, जिनमें सतारा से लेकर धारवाड़ और कोफाल का क्षेत्र था, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे और दत्താजी पंत के नियंत्रण में थे। इन तीन सूबों को पुनः परगनों और तालुकों में विभाजित किया गया था। शिवाजी को 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में छत्रपति की उपाधि मिली।मराठों के लिए छत्रपति एक राजा या सम्राट के सबसे करीबी समकक्ष थे। यह शब्द दो अलग-अलग शब्दों से आता है छत्र का अर्थ है एक प्रकार का मुकुट जिसे देवताओं या बेहद पवित्र पुरुषों द्वारा पहना जाता है। पटी का मतलब गुरु था। शिवाजी ने खुद को राजा या सम्राट बनने के लिए तैयार नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुद को अपने लोगों का रक्षक माना। बल्कि मेरा मानना है कि उनके लोगों ने उन्हें इस विशेष उपाधि से सम्मानित किया था।शिवाजी हिन्दू धर्म के रक्षक थे। उन्होंने धर्म की रक्षा में बहुत बड़ा काम किया। जन सेवा की, जनता में मुगलों का भय समाप्त किया उससे पहले दक्कन के सल्तनतों को छकाया। धार्मिक रूप से पीड़ितों को सहायता दी। उनका मान सम्मान बनाया। देवी देवताओं के मंदिरों को नष्ट होने से बचाया। आततायी म्लेच्छों को कष्ट दिया। अतः उन्हें जनता ने शिव का अवतार माना और धर्म ध्वज रक्षक कहे गए है। इसलिए मराठा ही नहीं, समस्त भारत में समस्त हिन्दू समाज हर जाति वर्ग का व्यक्ति उनको सम्मान देता है, देता रहेगा। आज भी महाराष्ट्र में लोग उनके नाम का राजनीतिक लाभ लेते है और काम औरंगजेब के करते है। लेकिन जल्दी ही ऐसे लोग पहचान लिए जाते है। शिवाजी का संघर्ष शक्तिशाली शोषक मुगल बादशाह औरंगजेब के विरुद्ध था। उन्होंने अपनी सेना को धर्म की रक्षा करना बालक, बड़े बूढ़े लोगों की, महिला की सहायता करने के आदेश दिये थे । जनता के धन की फसल की लूटपाट नहीं करने के आदेश थे। लेकिन लुटेरों को लूट सकते थे। इस लिए छापामार पद्धति अपनाकर मुगलों को भागने को मजबूर कर दिया और स्वतंत्र हिन्दू सुराज की स्थापना का संकल्प पूरा किया।

जब रामायण और महाभारत के सीरियल्स का जादू था

आज मैं आपको 80 के दशक के उस दौर में ले चलना चाहता हूं, जब भारत टेलीविजन के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा था। वह समय केवल मनोरंजन का नहीं, बल्कि सामूहिक अनुभवों का समय था। आज भले ही सैकड़ों चैनल और ओटीटी प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं, कार्यक्रमों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उस दौर की बात ही कुछ और थी। तब विकल्प कम थे, पर अपनापन अधिक था। पूरा देश एक समय, एक भावना और एक कहानी में बंध जाता था। वह केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि सामूहिक एकता और सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रतीक था। आज हम बात करेंगे उन धारावाहिकों की, जिन्होंने भारतीय जनमानस को टेलीविजन से इस तरह जोड़ दिया कि प्रसारण के समय सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था। उन दिनों दूरदर्शन ही एकमात्र चैनल हुआ करता था। मनोरंजन के साधन सीमित थे, लेकिन जो था, वह पूरे देश को एक सूत्र में बांध देता था। 1982 में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला लोकप्रिय कार्यक्रम चित्रहार लोगों के बीच अत्यंत प्रिय था। इसमें पुराने और नए हिंदी फिल्मों के गीत दिखाए जाते थे। इसका प्रसारण शाम के समय होता था, जब परिवार के सभी सदस्य दिनभर के काम से निवृत्त होकर एक साथ बैठते थे। टेलीविजन के सामने बैठना एक पारिवारिक अनुष्ठान जैसा बन गया था। हमें भली-भांति याद है दूरदर्शन का पहला लोकप्रिय धारावाहिक हम लोग, जो जुलाई 1984 में प्रारंभ हुआ। यह मध्यमवर्गीय परिवार की कहानी थी और लगभग डेढ़ सौ एपिसोड तक चला। इसके पात्र इतने वास्तविक लगते थे कि दर्शक उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानने लगे थे। इसके बाद 1986 में बुनियाद का प्रसारण हुआ, जो भारत विभाजन और उसके सामाजिक प्रभावों पर आधारित था। इस धारावाहिक ने लोगों के हृदय को गहराई से छुआ। फिर आया वह ऐतिहासिक क्षण-जनवरी 1987 में रामानंद सागर की रामायण का प्रसारण आरंभ हुआ। यह केवल एक धारावाहिक नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन बन गया था। रविवार सुबह 9:30 बजे जैसे ही इसका प्रसारण शुरू होता, पूरा देश थम-सा जाता था। सड़कें सूनी हो जाती थीं, नापन अधिक था। पूरा देश एक समय, एक भावना और एक कहानी में बंध जाता था। वह केवल मनोरंजन नहीं, बल्किनापन अधिक था। पूरा देश एक समय, एक भावना और एक कहानी में बंध जाता था। वह केवल मनोरंजन नहीं, बल्किदुकानें बंद रहती थीं और सार्वजनिक परिवहन लगभग खाली दिखाई देता था। लोगों की श्रद्धा इतनी प्रबल थी कि कई दर्शक प्रसारण से पहले स्नान करते, आरती उतारते और अपने टेलीविजन सेट को फूलों की माला पहनाते थे। भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल और माता सीता की भूमिका में दीपिका चिखलिया जहां भी जाते, लोग उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेते थे। उन्हें साक्षात देवी-देवता के रूप में देखा जाने लगा था। रावण की भूमिका निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी इतने प्रभावशाली थे कि उनके किरदार की मृत्यु के प्रसारण पर उनके गृह नगर में शोक का वातावरण बन गया था। उस समय सभी के घर में टेलीविजन नहीं हुआ करता था। सैकड़ों लोग एक ही मोहल्ले में एक टीवी सेट के सामने इकट्ठा होकर एपिसोड देखा करते थे। प्रसारण के समय महत्वपूर्ण सरकारी बैठकों तक को टाल दिया जाता था। बिजली विभाग पर भी विशेष दबाव रहता था, क्योंकि थोड़ी देर की बिजली कटौती भी लोगों के रोष का कारण बन जाती थी। रामायण के बाद बी.आर. चोपड़ा की महाभारत 1988 से 1990 के बीच प्रसारित हुई। इसका शीर्षक गीत मैं समय हूं। आज भी लोगों की स्मृतियों में ताजा है। भीष्म पितामह के रूप में मुकेश खन्ना, श्रीकृष्ण की भूमिका में नितीश भारद्वाज और दुर्योधन के रूप में पुनीत इस्सर ने अपने अभिनय से पात्रों को जीवंत कर दिया। महाभारत केवल एक पौराणिक कथा नहीं थी, बल्कि नीति, धर्म, राजनीति और मानवीय संबंधों की गहन व्याख्या थी। इसके संवाद इतने प्रभावशाली थे कि लोग उन्हें याद कर लिया करते थे। हर एपिसोड के बाद घरों में उस दिन की कथा पर चर्चा होती थी, मानो कोई पारिवारिक गोष्ठी चल रही हो। इन धारावाहिकों का प्रभाव इतना व्यापक था कि भारत में टेलीविजन सेटों की बिक्री में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। उन्होंने एक साझा राष्ट्रीय अनुभव का निर्माण किया, जिसमें लाखों लोग एक ही समय पर, एक ही कथा से जुड़ते थे। वह भारतीय सामाजिक इतिहास का एक स्वर्णिम कालखंड था, जिसने मनोरंजन को सांस्कृतिक चेतना से जोड़ दिया। यदि भारतीय टेलीविजन के इतिहास की बात करें तो इसकी शुरुआत सितंबर 1959 में नई दिल्ली से हुई थी। प्रारंभिक प्रसारण सीमित घंटों के लिए होता था, जबकि दैनिक नियमित सेवा 1965 में शुरू हुई। 1972 में इसका विस्तार मुंबई और अमृतसर तक हुआ। 1982 के एशियाई सैकड़ों चैनल और ओटीटी प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं, कार्यक्रमों की खेलों ने रंगीन टेलीविजन की शुरुआत कर देश में एक नया युग आरंभ किया। इसी पृष्ठभूमि में 80 का दशक भारतीय टेलीविजन का स्वर्णिम युग बन गया। आज भले ही सैकड़ों चैनल और ओटीटी प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं, कार्यक्रमों की कोई कमी नहीं सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रतीक था।

सम्पादकीय...

हमारी परवरिश का आईना

आज अक्सर सुनने को मिलता है आजकल के बच्चों में संस्कार नहीं रहे। यह वाक्य हम बड़े सहज भाव से कह देते हैं, मानो सारी जिम्मेदारी बच्चों की ही हो। किंतु यदि गंभीरता से विचार करें तो पाएंगे कि बच्चे तो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं; उन्हें जिस सांचे में ढाल दिया जाए, वे वैसा ही रूप धारण कर लेते हैं। ऐसे में प्रश्न यह नहीं कि बच्चों में संस्कार क्यों नहीं है, बल्कि यह है कि हमने उन्हें क्या सिखाया और कैसे सिखाया? संस्कार किसी पाठ्यपुस्तक का अध्याय नहीं होते, जिन्हें रटकर सीखा जा सके। वे परिवार के वातावरण से, माता-पिता के व्यवहार से और घर की परंपराओं से आत्मसात होते हैं। यदि घर में बड़ों का सम्मान होता है, सच्चाई को महत्व दिया जाता है और अनुशासन का पालन होता है, तो बच्चा स्वतः ही इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है। परंतु यदि घर में कटुता, असहिष्णुता, दिखावा और स्वार्थ का वातावरण हो, तो वही भावनाएँ बच्चों के व्यक्तित्व में उतर जाती हैं। आज की भागदौड़ भरी जीवनशैली ने परिवारों को समयहीन बना दिया है। माता-पिता अपनी जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि बच्चों के साथ संवाद के लिए समय नहीं निकाल पाते। परिणामस्वरूप बच्चे संस्कारों की शिक्षा घर से कम और बाहरी दुनिया से अधिक ग्रहण कर रहे हैं। मोबाइल, इंटरनेट और सामाजिक माध्यमों का प्रभाव इतना प्रबल है कि वे बच्चों के विचारों और व्यवहार को प्रभावित कर रहे हैं। यदि उन पर उचित निगरानी और मार्गदर्शन न हो, तो वे भ्रमित भी हो सकते हैं। दूसरा बड़ा कारण यह है कि हम स्वयं अपने आचरण में वह अनुशासन और मर्यादा नहीं रखते, जिसकी अपेक्षा बच्चों से करते हैं। हम बच्चों से सत्य बोलने को कहते हैं, परंतु स्वयं छोटी-छोटी बातों में असत्य का सहारा लेते हैं। हम उनसे बड़ों का सम्मान करने की अपेक्षा करते हैं, परंतु स्वयं अपने बुजुर्गों की उपेक्षा कर बैठते हैं। ऐसे में बच्चे दोहरे मानदंडों को देखकर भ्रमित हो जाते हैं और उनके भीतर विरोधाभास जन्म लेने लगता है। संस्कारों का ह्रास केवल पारिवारिक समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक चिंता का विषय है। जब एक पीढ़ी मूल्यों से दूर हो जाती है, तो उसका प्रभाव समाज के प्रत्येक क्षेत्र पर पड़ता है। इसलिए आवश्यक है कि हम आत्ममंथन करें और बच्चों को दोष देने के स्थान पर अपनी भूमिका को समझें। हमें चाहिए कि हम बच्चों के साथ समय बिताएँ, उनसे संवाद करें, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करें और अपने आचरण से उन्हें सही-गलत का भेद सिखाएँ। त्योहारों, पारिवारिक परंपराओं और सामाजिक दायित्वों में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करें। उन्हें केवल सफलता की दौड़ में आगे बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उन्हें संवेदनशील, सहृदय और नैतिक बनाना भी उतना ही आवश्यक है। बच्चे हमारे भविष्य की नींव हैं। यदि नींव मजबूत होगी तो समाज भी सुदृढ़ होगा। अतः आइए, हम स्वयं को आदर्श बनाकर बच्चों को संस्कारों की अमूल्य धरोहर सौंपें। याद रखिए बच्चे वही बनते हैं, जो वे देखते हैं।

आरएसएस और मुस्लिमों में बनते सेतु

इसी संदर्भ में संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता, राजवेंद्र यादव ने भी एक बड़े मारके की पुस्तक लिखी है, भारतीय मुस्लिमों की गौरव गाथाएं यह एक महत्वपूर्ण कृति है जिसमें भारत के मुस्लिम समाज के उन महान व्यक्तित्वों और योगदानों को रेखांकित किया गया है जिन्होंने राष्ट्र निर्माण, स्वतंत्रता संग्राम, शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, सेना और सामाजिक सुधार में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। इसमें राष्ट्र रक्षा को समर्पित वीर सैनिकों, कला-साहित्य और खेल जगत की विभूतियों के साथ-साथ सामाजिक सुधारकों को भी स्थान दिया गया है, जिन्होंने समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया। राम मंदिर, अयोध्या के संदर्भ में भी पुस्तक उन आवाज़ों को सामने लाती है जो शांतिपूर्ण समाधान और आपसी सद्भाव की पक्षधर थे। पुस्तक में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज़ादी तक मुस्लिम क्रांतिकारियों और नेताओं की भूमिका का उल्लेख है, जैसे, बहादुर शाह ज़फ़र, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, सर मुहम्मद इक़बाल, अशफाक उल्ला खां, सर सैयद अहमद खां, अशफाकुल्लाह खान, मौलाना हसरत मोहानी।

आरएसएस और मुस्लिम मिलन एक जटिल और बहुआयामी विषय है। इसमें ऐतिहासिक अविश्वास भी है और संवाद की संभावनाएं भी, जैसा कि आजकल हो रहा है। भारत जैसे बहुलतावादी देश में स्थायी समाधान का मार्ग संवाद, संवैधानिक मूल्यों और आपसी सम्मान से ही निकल सकता है।

2002 में आरएसएस से प्रेरित मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की स्थापना संघ नेता के सुदर्शन, मौलाना जमील अहमद इलयासी और उनके पुत्र उमैर इलियासी व अन्य मुस्लिम नेताओं के सौजन्य से हुई, जिसका उद्देश्य राष्ट्रवाद और सामाजिक समरसता के मुद्दों पर मुस्लिम समाज से संवाद बढ़ाना है। कई अवसरों पर आरएसएस प्रमुखों ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों और उलेमा से भेंट की है। मोहन भागवत ने विभिन्न मंचों पर यह कहा कि भारत में रहने वाले सभी लोग सांस्कृतिक रूप से एक ही राष्ट्र का हिस्सा हैं। वे मदरसे भी गए और मुसलमानों के विरुद्ध एक भी गलत शब्द नहीं बोला। बावजूद इसके कि अधिकतर मुस्लिम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मुस्लिम विरोधी और साम्प्रदायिक समझते चले आ रहे हैं, संघ ने जिस प्रकार से मुस्लिम वर्ग के हित में जो कार्य किए हैं उससे सभी को अचंभा भी हुआ है और खुशी भी,विशेष रूप से मुस्लिमों को। मुसलमानों में आजादी के बाद कुछ राजनीतिक वर्गों द्वारा यह दुर्भावना, भ्रांति और बदगुमानी फैलाई गई कि हिंदू महासभा, संघ, जनसंघ, आरएसएस और इनसे जुड़े सभी संगठन, मुसलमानों के दुश्मन हैं और इनको समाप्त करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत धारणा थी, मगर मुस्लिमों के कुछ स्वयंभू नेताओं ने अपनी दुकानों को चमकाने हेतु कौम को इस प्रकार भड़काया और भटकाया कि उसके और मुस्लिमों के मध्य एक खाई पैदा हो गई।

2014 के चुनाव से पूर्व इस बात का प्रचार किया गया कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों के विरुद्ध ऐसे ही दंगे भड़का देंगे, जैसे गुजरात में! आरएसएस और मुस्लिम मिलन का विषय भारत की सामाजिक-राजनीतिक चर्चा में लंबे समय से महत्वपूर्ण रहा है। यह संबंध टकराव, संवाद, पहल और आपसी अविश्वास इन सभी चरणों से गुजरा है, मगर फिर भी मुस्लिमों की एक छोटी संख्या ने न केवल भाजपा को वोट दिया बल्कि सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत के इस कथन को भी सराहा कि भारत मुस्लिमों के सहयोग के बिना जगत गुरु नहीं बन सकता। एक बार उन्होंने यह भी कहा कि हम मुसलमानों के बिना भारत की कल्पना भी नहीं कर सकते। संघ के सौजन्य से दो ऐसी पुस्तकें प्रकाशित हुईं कि कोई विश्वास नहीं कर सकता कि संघ ऐसा करेगा। इस सरकार के दौर में सबको चकित करने वाली पहली ऐसी पुस्तक थी, वैचारिक पहल- एक व्यावहारिक समन्वय, जिसके लेखक ख्वाजा इफ्तेखार अहमद हैं और जिसका विमोचन स्वयं सरसंघ चालक ने यह कह कर किया था कि अपने जीवन में मुस्लिम-संघ के बीच सेतु बनाने वाली किसी मुस्लिम द्वारा यह पहली ऐसी पुस्तक है। पुस्तक के प्रकाशित होते ही हिंदुओं और मुस्लिमों में न केवल पुल बने, बल्कि मुसलमानों के एक बड़े तबके में संघ और उनके के बीच गलत फहमियां दूर होने लगी है और मुस्लिम संघ से जुड़ कर राष्ट्र निर्माण के कार्य में धूम से लगे हुए हैं। इसी संदर्भ में संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता, राजवेंद्र यादव ने भी एक बड़े मारके की पुस्तक लिखी है, भारतीय मुस्लिमों की गौरव गाथाएं यह एक महत्वपूर्ण कृति है जिसमें भारत के मुस्लिम समाज के उन महान व्यक्तित्वों और योगदानों को रेखांकित किया गया है जिन्होंने राष्ट्र निर्माण, स्वतंत्रता संग्राम, शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, सेना और सामाजिक सुधार में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। इसमें राष्ट्र रक्षा को समर्पित वीर सैनिकों, कला-साहित्य और खेल जगत की विभूतियों के साथ-साथ सामाजिक सुधारकों को भी स्थान दिया गया है, जिन्होंने समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया। राम मंदिर, अयोध्या के संदर्भ में भी पुस्तक उन आवाज़ों को सामने लाती है जो शांतिपूर्ण समाधान और आपसी सद्भाव की पक्षधर थे। पुस्तक में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज़ादी तक मुस्लिम क्रांतिकारियों और नेताओं की भूमिका का उल्लेख है, जैसे, बहादुर शाह ज़फ़र, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, सर मुहम्मद इक़बाल, अशफाक उल्ला खां, सर सैयद अहमद खां, अशफाकुल्लाह खान, मौलाना हसरत मोहानी। मुस्लिम समाज के मुख्य चेहरे, जैसे, मिर्जा ग़ालिब, एपीजे अब्दुल कलाम, मुहम्मद अजहरुद्दीन आदि, जिसका विमोचन संघ के वरिष्ठ नेता, इंद्रेश कुमार ने किया था। इन पुस्तकों के द्वारा ही नहीं, बल्कि अपने ट्रैक रिकॉर्ड द्वारा भी संघ ने खास तौर से प्रमाणित किया है कि किस प्रकार से उसकी कार्य प्रणाली में मुस्लिम वर्ग को शामिल किया जा रहा है। संवाद का सिलसिला लगातार चल रहा है और उसके खुशगवार

यूजीसी बिल 2026 का विवाद

सुरेश सिंह बैस शाश्वत

यूजीसी (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) विनियम, 2026, जिसे सामान्यतः यूजीसी बिल 2026 या इक्विटी रेगुलेशन कहा जा रहा है, वर्तमान में भारतीय शिक्षा जगत और सामाजिक विमर्श के केंद्र में है। इस कानून का उद्देश्य जाति-आधारित भेदभाव को समाप्त करना है, लेकिन इसके कुछ प्रावधानों ने हिंदू समाज के भीतर आंतरिक दरार और बिखराव की आशंकाओं को जन्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तात्कालिक रूप से इस पर रोक लगाकर पुनः संशोधन हेतु विचार के लिए भेजना अति आवश्यक था। जो भारत और भारत के लोगों में बिखराव को रोकने के लिए महती कदम साबित हुआ है। यूजीसी बिल 2026 सामाजिक सामंजस्य बनाम आंतरिक बिखराव के द्योतक के रूप में सामने आया। जनवरी 2026 में अधिसूचित यह नया नियम उन शिक्षण संस्थानों (में अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ अब अन्य पिछड़ा वर्ग को भी भेदभाव-रोधी दायरे में लाता है। जहाँ एक पक्ष इसे सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम मान रहा है, वहीं दूसरा पक्ष इसे हिंदू समाज के विभिन्न वर्गों के बीच अविश्वास पैदा करने वाला उपकरण मान रहा है। बिल के विरोध में तर्क दिया जा रहा है कि यह नियम हिंदू समाज के भीतर अगड़ी जातियों और पिछड़ी जातियों के बीच खाई को और चौड़ा कर सकता है। दुरुपयोग का भय, आलोचकों का मानना है कि भेदभाव की परिभाषा इतनी व्यापक है कि इसे किसी भी शैक्षणिक विमर्श या व्यक्तिगत मतभेद के खिलाफ हथियार बनाया जा सकता है। सांस्कृतिक प्रभाव, हिंदू समाज की एकता के पैरोकारों का तर्क है कि ऐसे सख्त कानूनी प्रावधानों से संस्थानों में एक ऐसा माहौल बनेगा जहाँ छात्र और शिक्षक एक-दूसरे को जातिगत चश्मे से देखेंगे, जिससे स्वाभाविक भाईचारा प्रभावित होगा। झूठी शिकायतों पर दंड के प्रावधान का हटना,विवाद का एक बड़ा कारण यह है कि 2025 के मसौदे में झूठी या द्वेषपूर्ण शिकायतों पर दंड का प्रावधान था, जिसे अंतिम 2026 नियमों से हटा दिया गया है चिंता का विषय है कि सामान्य वर्ग के छात्रों और संगठनों का कहना है कि बिना किसी सुरक्षा कवच के, यह कानून लक्षित उत्पीड़न का जरिया बन सकता है, जिससे समाज में प्रतिशोध की भावना पनपेगी। इक्विटी कमेटी की संरचना और प्रतिनिधित्व में भी संशय उत्पन्न करने वाला साबित हुआ। नए नियमों के तहत प्रत्येक संस्थान को 10 सदस्यीय इक्विटी कमेटी बनानी होगी, जिसमें कम से कम 50 फीसदी सदस्य आरक्षित वर्गों (SC/ ST/ OBC/ महिला) से होंगे। प्रशासनिक असंतुलन भी नजर आया है। कुछ शिक्षाविदों का मानना है कि यह संरचना योग्यता के बजाय पहचान को प्राथमिकता देती है, जिससे हिंदू समाज के भीतर ही प्रशासनिक पदों को लेकर खींचतान शुरू हो सकती है। सामाजिक तनाव और विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए, फरवरी 2026 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन विनियमों पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि भारत की एकता हमारे शैक्षणिक संस्थानों में झलकनी चाहिए और वह इसकी संवैधानिक वैधता की जांच कर रहा है। हिंदू समाज पारंपरिक रूप से सामाजिक सुधारों और विखंडन की चुनौतियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता रहा है। यूजीसी बिल 2026 का उद्देश्य भले ही समावेशिता हो, लेकिन इसके कार्यान्वयन के तरीके ने समाज के एक बड़े हिस्से में असुरक्षा का भाव भर दिया है। यदि इन नियमों को बिना संतुलन और सुरक्षा के लागू किया जाता है, तो यह शैक्षणिक परिसरों को वैचारिक और जातिगत युद्ध के मैदान में बदल सकता है, जो अंततः व्यापक हिंदू समाज की एकता के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इस यूजीसी बिल 2026 के विवादास्पद कानूनी प्रावधान और उनके प्रभाव को अगर एक नजर में देखे तो भेदभाव की व्यापक और अस्पष्ट परिभाषा। विनियम के खंड 3 ( ) के तहत भेदभाव की परिभाषा को केवल भौतिक उत्पीड़न तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि इसमें मानसिक प्रताड़ना और अपमानजनक व्यवहार को भी शामिल किया गया है। यही मूल कारण है जो विवाद का कारण बना। आलोचकों का तर्क है कि अपमान एक व्यक्तिपरक शब्द है। कक्षा में किसी ऐतिहासिक तथ्य पर चर्चा या किसी छात्र के शैक्षणिक प्रदर्शन की आलोचना को भी इस कानून के तहत जातिगत अपमान के रूप में पेश किया जा सकता है। इससे हिंदू समाज के भीतर छात्रों और शिक्षकों के बीच एक अघोषित दूरी पैदा होने का डर है। धारा 7- झूठी शिकायत पर दंड के प्रावधान का स्पष्ट अभाव भी भारतीय समाज में गलत संदेश संदेह के रूप में सामने आया। 2023 के शुरुआती मसौदे में एक उप-धारा थी जिसमें स्पष्ट था कि यदि कोई शिकायत दुर्भावनापूर्ण या झूठी पाई जाती है, तो शिकायतकर्ता पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। जबकि 2026 के यूजीसी बिल में इसे पूरी तरह से बदलाव करते हुए अंतिम कानून में इस सुरक्षात्मक प्रावधान को हटा दिया गया है। इसका प्रभाव गलत रूप में सामने आया।

इसके कारण सामान्य वर्ग के छात्रों और शिक्षकों में यह धारणा बन गई है कि उन्हें बिना किसी साक्ष्य के फंसाया जा सकता है और उनके पास बचाव का कोई कानूनी रास्ता नहीं होगा। यह कानूनी असमानता समाज के विभिन्न वर्गों के बीच अविश्वास को गहरा कर रही है। वहीं इक्विटी कमेटी की असीमित शक्तियाँ (धारा 5.2)के तहत प्रत्येक कॉलेज और विश्वविद्यालय में एक इक्विटी कमेटी का गठन अनिवार्य है। इस कमेटी को न केवल जाँच करने बल्कि दोषी पाए जाने पर छात्र का निलंबन या शिक्षक की पदोन्नति रोकने की सिफारिश करने का भी अधिकार है।इससे आमजन में पक्षपात का डर पैदा हुआ,क्योंकि इस कमेटी में 50% से अधिक प्रतिनिधित्व आरक्षित वर्गों के लिए अनिवार्य है, इसलिए दूसरे पक्ष को डर है कि निर्णय योग्यता के बजाय पहचान के आधार पर लिए जा सकते हैं। पदोन्नति और नियुक्तियों पर भी विघटनकारी असर देखने को मिला (धारा 8)इस बिल में एक प्रावधान यह भी है कि यदि किसी संस्थान के विरुद्ध भेदभाव की शिकायतें बार-बार आती हैं, तो यूजीसी उस संस्थान के अनुदान को रोक सकता है। संस्थान के प्रशासन पर यह दबाव रहेगा कि वे विवादों से बचने के लिए नियुक्तियों में मेरिट के बजाय सामाजिक तुष्टीकरण को प्राथमिकता दें। इससे हिंदू समाज के प्रतिभावान युवाओं में अलगाव की भावना पैदा हो सकती है। किसी एक व्यक्ति की गलती के लिए पूरे विभाग या संस्थान को दंडित करना।

डर के कारण जाति, धर्म या समाज पर खुले संवाद का बंद होना। यह सब प्रावधान लोगों में डर का कारण बना। विशेषज्ञों का मानना है कि हिंदू समाज में बिखराव को रोकने के लिए सरकार को इस बिल में न्यायिक संतुलन लाना होगा। इसमें झूठी शिकायतों के खिलाफ कड़ी सजा और भेदभाव की अधिक स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ परिभाषा शामिल होनी चाहिए।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने करन ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, सराय पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2011/...)

कानपुर नगर में 22 फरवरी को वृहद विधिक सेवा एवं जागरूकता शिविर का आयोजन

कानपुर नगर।

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जनपद कानपुर नगर में आयोजित होने वाले वृहद विधिक सेवा एवं जागरूकता शिविर की तैयारियों को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश अनमोल पाल की अध्यक्षता में जनपद न्यायालय परिसर के प्रथम तल स्थित नवीन सभागार में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/नोडल अधिकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विनय सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेष बहादुर निषाद, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पियूष सिद्धार्थ, प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिनव तिवारी, अपर सिविल न्यायाधीश/ प्रभारी सचिव (नोडल) कर्णिका अवध, मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। अध्यक्षता करते हुए जनपद न्यायाधीश ने बताया कि वृहद विधिक सेवा एवं जागरूकता शिविर का आयोजन 22 फरवरी 2026, रविवार को प्रातः 10:00 बजे छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के सभागार में किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि शिविर में भाग लेने वाले सभी विभाग अपनी-अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं से

संबंधित स्टॉल एवं प्रदर्शनी समय से पूर्व स्थापित कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें, जिससे आमजन को अधिकतम लाभ मिल सके। उन्होंने संबंधित विभागों को लाभार्थियों के आवागमन की समुचित व्यवस्था पूर्व से सुनिश्चित करने तथा कार्यक्रम के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश भी दिए, ताकि अधिक से अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित हो सके। मुख्य विकास अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी प्रभावी ढंग से आमजन तक पहुंचाने के लिए सभी विभाग स्वयं की निगरानी में स्टॉल स्थापित करें और कर्मचारियों की ड्यूटी पूर्व निर्धारित कर लें, जिससे शिविर में आने वाले लाभार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

प्रचार वाहन एवं जागरूकता रैली को दिखाई गई हरी झंडी

समीक्षा बैठक के उपरांत जनपद न्यायाधीश अनमोल पाल ने शिविर के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए प्रचार वाहन एवं जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह प्रचार वाहन जनपद के प्रमुख मार्गों, बाजारों एवं सार्वजनिक स्थलों पर भ्रमण कर आमजन को शिविर की तिथि, स्थान एवं उपलब्ध सेवाओं की जानकारी देगा। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश ने कहा कि शिविर का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक निःशुल्क विधिक सहायता एवं शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने आमजन से अधिकाधिक संख्या में शिविर में सहभागिता करने की अपील की। रैली के माध्यम से विधिक अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत, महिला एवं बाल संरक्षण संबंधी प्रावधानों तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान कर समाज में विधिक जागरूकता को सुदृढ़ किया जाएगा।

हनुमान मंदिर के सौन्दर्यकरण के लिए टीम ने किया भ्रमण

मुरादाबाद। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा मूंढापांडेय

ब्लॉक के ग्राम भीतखेड़ा स्थित हनुमान मंदिर के सौंदर्यीकरण एवं विकास के लिए मंदिर प्रांगण का सर्वे किया गया। कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह से मिलकर भीतखेड़ा स्थित हनुमान मंदिर के सौंदर्यीकरण एवं विस्तार की मांग की थी। करीब 2 करोड़ की इस परियोजना से मंदिर में बहुउद्देशीय हॉल, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, यात्री बेंच, म्यूरल, लैंडस्केपिंग आदि कार्य कराए जाएंगे। सर्वे उपरांत परियोजना की स्वीकृति होते ही वर्तमान वित्तीय वर्ष में धन आवंटन के बाद हनुमान मंदिर के सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू हो जाएगा। मंदिर के सौंदर्यीकरण और सुविधाओं के विकास से न केवल श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी बल्कि क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। सर्वे टीम में शामिल रहे पर्यटन विभाग सौरभ सिंह और आर्किटेक्ट सादिक खान द्वारा सर्वे किया गया। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख मूंढापांडेय डॉ नवदीप यादव, जयवीर सिंह, प्रधानलाल श्यामलाल, नेपाल सिंह, मंडल अध्यक्ष महेंद्र सैनी, विपिन, राकेश कुमार आदि मौजूद रहे।

कानपुर नगर में 2026 तक बाल श्रम मुक्त बनाने की कार्ययोजना पर कार्यशाला

कानपुर।

सरसैयाघाट स्थित नवीन सभागार में जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में जनपद को वर्ष 2026 तक बाल श्रम मुक्त बनाने हेतु जिला कार्ययोजना को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला श्रम विभाग एवं एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि बाल श्रम उन्मूलन के लिए सभी बच्चों का विद्यालयों में प्रवेश सुनिश्चित कर उनका ठहराव कराया जाना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही अन्य विभागों के अधिसूचित निरीक्षकों द्वारा नियमित बाल श्रम निरीक्षण एवं पुनर्वास की कार्वाई की जाए। उन्होंने सभी खण्ड विकास अधिकारियों, तहसीलदारों सहित संबंधित अधिकारियों को बाल श्रमिक नियोजन के मामलों में सख्त कार्रवाई

के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि बाल श्रम उन्मूलन एवं पुनर्वास के लिए गठित जिला टास्क फोर्स की नियमित बैठकें आयोजित की जाएं। श्रम विभाग के राज्य समन्वयक सैयद रिजवान अली ने कार्यशाला में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2027 तक प्रदेश के सभी जनपदों को बाल श्रम मुक्त करने तथा चयनित आकांक्षी जनपदों को दिसंबर 2026 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने का निर्धारण किया गया है। उन्होंने कानपुर नगर को बाल श्रम मुक्त बनाने के लिए सभी विभागों के समन्वय, संयुक्त कार्रवाई और एक मंच पर कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही समस्त ईंट-भट्ठों में कार्यरत श्रमिकों के पंजीकरण पर भी विशेष जोर दिया गया। आगामी एक वर्ष की रणनीति पर विस्तृत चर्चा कर कार्ययोजना तैयार की गई। बैठक में उपस्थित व्यापार मंडल एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने आगामी दो माह में अपने अधीन व्यापारिक प्रतिष्ठानों में बाल श्रम न कराने हेतु अभियान चलाने तथा ÷बाल श्रम मुक्त प्रतिष्ठान के स्टीकर लगाने की घोषणा की। कार्यक्रम में संस्था के कार्यक्रम समन्वयक अमरेंद्र कुमार एवं राष्ट्रीय प्रशिक्षक अभय अवस्थी ने संस्था के मिशन एवं विजन की जानकारी दी।

उन्होंने बाल श्रम उन्मूलन के लिए विभागीय समन्वय (कन्वर्जेंस) के माध्यम से प्रभावी कार्यवाही पर बल देते हुए सभी संगठनों से सहयोग की अपील की। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के प्रतिनिधि उमेश गुप्ता ने बाल श्रम उन्मूलन एवं पुनर्वास कार्यों में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका पर प्रकाश डाला और बताया कि आपसी समन्वय से इस समस्या का प्रभावी समाधान संभव है। कार्यक्रम में सहायक श्रमायुक्त राम लखन, श्रम विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायती राज, समाज कल्याण, महिला कल्याण, पुलिस, एएचटीयू, कौशल विकास मिशन, चाइल्ड वेलफेयर समिति सहित विभिन्न विभागों एवं संगठनों के प्रतिनिधियों ने सहभागिता।

बहराइच में बोर्ड परीक्षा के लिए स्थापित कन्ट्रोल रूम का डीएम ने किया निरीक्षण

बहराइच।

माध्यमिक शिक्षा परिषद उ.प्र. प्रयागराज द्वारा आयोजित आयोजित हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा 2026 को नकलविहीन तथा सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराये जाने तथा सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जनसुनवाई कक्ष में कमाण्ड सेन्टर (परीक्षा कन्ट्रोल रूम) स्थापित किया जा रहा है। जनपद के 122 परीक्षा केन्द्रों पर 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 तक सम्पन्न होने वाली बोर्ड परीक्षाओं की सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी की जा रही है। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने जिला विद्यालय निरीक्षक सर्वदानंद व अन्य अधिकारियों के साथ कन्ट्रोल रूम का निरीक्षण करते हुए निगरानी के लिए स्थापित की गई टीवी स्क्रीन का निरीक्षण किया तथा तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों से जानकारी प्राप्त करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिये। कन्ट्रोल रूम के निरीक्षण के दौरान डीएम ने बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने रहे छात्र-छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए निर्भिक होकर परीक्षा में सम्मिलित होने का आह्वान किया। डीएम श्री त्रिपाठी ने बताया कि मा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी व शासन के निर्देशानुसार जनपद में शुचितापूर्ण वातावरण में नकलविहीन बोर्ड परीक्षा सम्पन्न कराना जिला प्रशासन की शीर्ष प्राथमिकता है।

डीएम ने बताया कि सभी 122 परीक्षा केन्द्रों पर केन्द्र व्यवस्थापक के साथ-साथ अतिरिक्त केन्द्र व्यवस्थापक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट, नोडल अधिकारियों के साथ-साथ प्रशासनिक अधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

डीएम ने बताया कि कन्ट्रोल रूम के माध्यम सघन निगरानी रखी जा रही है। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर अमिता यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

रमजान-होली के मद्देनज़र बिजली-पानी के रहें व्यापक इंतज़ाम

मुरादाबाद। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड की मुरादाबाद महानगर इकाई ने मुक़द्दस माहे रमज़ान होली एवं ईद उल फितर पर सफाई शांति पेयजल यातायात सुरक्षा एवं विद्युत व्यवस्था के कड़े प्रबंध किए जाने की मांग उठाई है इस संबंध में महानगर अध्यक्ष रज़ि उद्दीन खां एडवोकेट के नेतृत्व में एक ज्ञापन जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रिंस वर्मा को पेश किया गया। ज्ञापन में कहा गया है कि मुक़द्दस माहे रमजान का आगाज़ 19 फरवरी से हो रहा है एवं होली का त्योहार 4 मार्च को मनाया जाएगा होली एवं रमज़ान हिंदू मुस्लिम धर्म के बड़े त्यौहार हैं रमज़ान के महीने में रोज़े व नमाज के समय वाहन चेकिंग से रोज़ेदारों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है मांग उठाई गई है कि शाम 4.×0 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक वाहन चेकिंग पर पूर्णत्या प्रतिबंध लगाया जाए खस्ता हाल सड़कों की मरम्मत कराई जाए होली एवं रमजान के मौके पर समस्त शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित मंदिर मस्जिदों के निकट सफाई व्यवस्था व सहरी व इफ्तार के समय नियमित बिजली पानी की आपूर्ति करने व मंदिर मस्जिदों के पास स्ट्रीट लाइट लगाए जाने की मांग उठाई गई है ज्ञापन के माध्यम से इस बात पर भी जोर दिया गया है कि रमजान माह में ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ जाती है।

सपा मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड ने सौंपा ज्ञापन

लिहाज़ा यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए कड़े प्रबंध किए जाएं एवं असामाजिक तत्वों पर कड़ी नज़र रखी जाए। इस दौरान औरंगज़ेब अली, शानू फैज़ खान मोहम्मद रेहान मीम फैसल ज़की खान मोहम्मद सलमान समीर अहमद मोहम्मद इमरान राशिद अली एवं अबुल फैज आदि पदाधिकारी मौजूद रहे।

सेना की युद्धक तैयारी को बेहतर बनाएगा एआई; हथियार बनेंगे स्मार्ट, बढ़ेगी सटीकता

नई दिल्ली । इंडियन आर्मी अब टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर कई बड़ी पहल कर रही है। राजधानी के भारत मंडपम में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान सेना ने साफ कर दिया कि आने वाले समय की लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जीती जाएगी। बुधवार को स्मार्टाइजिंग द किल चेन विषय पर हुए एक खास सेमिनार में सेना के वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग जगत के दिग्गज और बड़े शिक्षण संस्थानों के विशेषज्ञ जुटे। इसका मकसद था, कैसे एआई के जरिए हथियारों, वाहनों, ड्रोन और दूसरे सैन्य प्लेटफॉर्म्स को इतना स्मार्ट बनाया जाए कि युद्ध के हर चरण में तेजी, सटीकता और प्रभावशीलता बढ़े। एआई की मदद से अब मशीनें पहले ही बता देंगी कि कौन सा सिस्टम कब खराब हो सकता है, किस हिस्से में दिक्कत आने वाली है और कहां संसाधन पहले से भेजने होंगे। यानी अब मरम्मत बाद में नहीं, पहले से तैयारी होगी। यहां डीजी ईएमई लेफ्टिनेंट जनरल राजीव कुमार साहनी ने कहा कि उद्योग जगत के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर ऑपरेशनल सटीकता प्रभावी बनाने का बड़ा अवसर है। बड़ी मात्रा में सेंसर से मिलने वाले डेटा को कार्रवाई योग्य जानकारी में बदला जा सकता है। उभरते खतरों का पहले से अनुमान लगाया जा सकता है और पुराने हथियार सिस्टम को आधुनिक, डेटा-सक्षम और स्मार्ट प्लेटफॉर्म में अपग्रेड किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्नत एनालिटिक्स के जरिए इंजीनियरिंग सपोर्ट को तेज करना जरूरी है, ताकि ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स अधिक मजबूत और सक्रिय बन सके। साथ ही उन्होंने भविष्य के युद्ध में निर्णायक बढ़त हासिल करने के लिए मानव रहित हवाई प्रणालियों, काउंटर-यूएएस सिस्टम और रोबोटिक प्लेटफॉर्म्स में एआई के एकीकरण पर भी विस्तार से चर्चा की। सेना मौजूदा हथियार सिस्टम और प्लेटफॉर्म्स को भी स्मार्ट बना रही है। उनमें सेंसर लगाए जा रहे हैं। इससे बिना ज्यादा खर्च किए मौजूदा संसाधनों की ताकत कई गुना बढ़ाई जा सकेगी। सेमिनार में यह भी चर्चा हुई कि ड्रोन, काउंटर-ड्रोन सिस्टम और रोबोटिक प्लेटफॉर्म्स में एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे स्पष्ट है कि भविष्य के युद्धों में इंसान से ज्यादा मशीनों की भूमिका होगी और जो सेना टेक्नोलॉजी में आगे होगी, वही बढ़त बनाएगी। लॉजिस्टिक्स यानी सप्लाई सिस्टम को भी पूरी तरह एआई से जोड़ने की तैयारी है। कौन सा स्पेयर पार्ट कब खत्म होगा, किस फॉर्मेशन में कितनी जरूरत पड़ेगी, किस सिस्टम को कब सर्विस की जरूरत है, यह सब पहले से अनुमान लगाकर संसाधन भेजे जाएंगे। इससे डाउनटाइम कम होगा और ऑपरेशनल टेंपो बना रहेगा। सेना के अनुसार सबसे अहम बात यह रही कि अब इंजीनियरिंग सपोर्ट सीधे कमांड फैसलों से जुड़ा होगा। कमांडर को रियल टाइम में पता होगा कि किस यूनिट के पास कौन सा उपकरण पूरी तरह तैयार है और कौन सा सिस्टम मेंटेनेंस में है।

एआई समिट प्रचार का तमाशा बन गया- राहुल

नई दिल्ली । कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में एक निजी विश्वविद्यालय द्वारा चीन में निर्मित रोबोटिक कुत्ते को प्रदर्शित किए जाने का हवाला देते हुए बुधवार को आरोप लगाया कि सरकार द्वारा आयोजित यह बड़ा कार्यक्रम सिर्फ पीआर (प्रचार) का तमाशा बन गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने एक्स पर पोस्ट किया, भारत की प्रतिभा और डेटा का उपयोग करने के बजाय, एआई शिखर सम्मेलन अव्यवस्थित तरीके से पीआर का तमाशा बन गया है। भारतीय डेटा बिक्री के लिए उपलब्ध है और चीनी उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस ने पोस्ट किया, मोदी सरकार ने देश की छवि को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है, उन्होंने एआई को मजाक बनाकर रख दिया है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम अपनी डेटा शक्ति को देखते हुए विश्व के अगुवा बन सकते हैं। गलगोटिया विश्वविद्यालय ने दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में 350 करोड़ रुपये की एआई परियोजनाओं और एक रोबोटिक कुत्ते का प्रदर्शन किया। खबरों के अनुसार, ओरायन नाम का यह रोबोट चीन निर्मित पाया गया, जिसके कारण विवाद खड़ा हो गया। सूत्रों का कहना है कि विवाद के बीच गलगोटिया विश्वविद्यालय को अपना स्टॉल तुरंत खाली करने के लिए कह दिया गया है। इसमें प्रदर्शित प्रौद्योगिकी की उत्पत्ति और स्वामित्व पर सवाल उठ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, विश्वविद्यालय से तुरंत प्रदर्शनी स्थल छोड़ने को कहा गया। आलोचकों का कहना था कि वह विश्वविद्यालय का स्वदेशी नवाचार नहीं है बल्कि चीन में बना एक रोबोट है।

भारतीय नौसेना देश के समुद्री हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह सतर्क है - राष्ट्रपति मुर्मू

विशाखापत्तनम ।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विशाखापत्तनम में बुधवार को अंतरराष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा के दौरान कहा कि भारतीय नौसेना देश के समुद्री हितों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह सतर्क रहने के साथ-साथ व्यापक समुद्री वाणिज्य गतिविधियों की स्थिरता में भी योगदान दे रही है। बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना के युद्धपोत पर सवार होकर विशाखापत्तनम तट पर अंतरराष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा (इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू.... आईएफआर) की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय नौसेना समुद्र में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों और खतरों के खिलाफ रक्षा और प्रतिरोध के एक विश्वसनीय साधन के रूप में क्षेत्र में तैनात है। मुर्मू ने कहा, भारतीय नौसेना देश के समुद्री हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह सतर्क है और व्यापक समुद्री वाणिज्यिक गतिविधियों की स्थिरता में योगदान दे रही है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय नौसेना दुनिया भर की नौसेनाओं के साथ सद्भावना को बढ़ावा देने और विश्वास, भरोसे व दोस्ती का सेतु बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राष्ट्रपति के अनुसार, विशाखापत्तनम का समुद्री इतिहास गौरवशाली रहा है। उन्होंने कहा कि आज का आयोजन विशाखापत्तनम के निरंतर नौसैनिक महत्व को रेखांकित करता है। भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसेना कमान (ईएनसी) का मुख्यालय विशाखापत्तनम में स्थित है। भारत और उसके मित्र देशों की नौसेनाओं के युद्धपोतों के प्रभावशाली बेड़े और नौसैनिकों के प्रदर्शन को देखकर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने उन्हें बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि आईएफआर समुद्री परंपराओं के प्रति राष्ट्रों के बीच एकता, विश्वास और सम्मान को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के जहाज और अलग-अलग देशों के नाविक एकजुटता की भावना का प्रदर्शन करते हैं। मुर्मू ने समुद्रों के साथ भारत के संबंधों पर कहा कि यह संबंध सदियों पुराने, गहरे और स्थायी हैं। उन्होंने महासागरों को भारत के लिए वाणिज्य, संपर्क और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का मार्ग बताया। राष्ट्रपति ने कटक में कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होने वाले सप्ताह के दौरान उत्साहपूर्वक मनाए जाने वाले बाली यात्रा उत्सव का उल्लेख करते हुए कहा कि यह त्योहार वर्तमान ओडिशा के प्राचीन नाविकों के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति है। उन्होंने रेखांकित किया कि यह उत्सव प्राचीन कलिंग काल से विभिन्न उद्देश्यों के लिए दक्षिण-पूर्व एशिया की नियमित समुद्री यात्राओं की परंपरा को परिलक्षित करता है। राष्ट्रपति ने कहा, इन यात्राओं ने व्यापार और वस्तुओं, विचारों और मूल्यों के आदान-प्रदान और उनकी भावना में योगदान दिया है, जिसने पूरे क्षेत्र में एक साझा सांस्कृतिक चेतना को आकार दिया। मुर्मू ने कहा कि यह बेड़ा समीक्षा भारत के महासागर के एकीकरण की भावना को आगे बढ़ाती है, जिसका अर्थ इस क्षेत्र में सुरक्षा और विकास की पारस्परिक तथा ऐतिहासिक उन्नति है।

सीएम योगी ने 5100 परिवारों को दिया तोहफा, एक क्लिक से सीधे खातों में पहुंचे एक-एक लाख रुपये

लखीमपुर। जिला नगरीय विकास अभिकरण के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 को जिले में बड़ी गति मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वन क्लिक के माध्यम से जिले के 5100 लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रति लाभार्थी एक-एक लाख रुपये की धनराशि स्थानांतरित की गई। धनराशि सीधे खातों में पहुंचने से पात्र परिवारों में उत्साह का माहौल है और अपने पक्के घर का सपना साकार होने की उम्मीद जगी है। एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने स्पष्ट किया है कि प्राप्त धनराशि से आवास का निर्माण नियमानुसार ही कराया जाएगा। प्रत्येक लाभार्थी को न्यूनतम 30 वर्गमीटर तथा अधिकतम 45 वर्गमीटर क्षेत्रफल में ही मकान बनवाना होगा। यह भी अनिवार्य किया गया है कि आवास का निर्माण केवल भूतल पर ही किया जाए। किसी भी स्थिति में प्रथम या द्वितीय तल पर निर्माण को मान्य नहीं माना जाएगा। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर अवमुक्त धनराशि की वसूली की जाएगी। निर्माण की गुणवत्ता को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। लाभार्थियों को हर हाल में आवास की छत आरसीसी की ही डलवानी होगी, ताकि भवन सुरक्षित और टिकाऊ बने। संबंधित विभाग द्वारा समय-समय पर निर्माण कार्य की निगरानी भी की जाएगी।

गौरव गोगोई ने हिमंता बिस्वा सरमा को बताया असम का जिन्ना, कहा- हिंदू सर्टिफिकेट बांटना बंद करें

नई दिल्ली । असम में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा ने पार्टी इस्तीफा दे दिया. उनके बीजेपी में शामिल होने को लेकर असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने कहा कि इसका कोई भी असर चुनावी संभावनाओं पर नहीं होगा. गौरव गोगोई ने कहा कि हिमंता बिस्वा सरमा असम के जिन्ना हैं. असम के सीएम ने इससे पहले ने कहा था कि भूपेन बोरा 22 फरवरी को बीजेपी में शामिल होंगे. गौरव गोगोई ने बुधवार (18 फरवरी 2026) को कहा कि सत्ताधारी बीजेपी में शामिल होने वाले लोग अपने राजनीतिक सफर में महत्वहीन हो गए हैं और भूपेन बोरा का भी यही हाल होगा. उन्होंने कहा, हम सर्बानंद सोनोवाल और कई अन्य लोगों का उदाहरण देख सकते हैं. एजीपी पार्टी (सोनोवाल की पिछली पार्टी) विलुप्त होने की कगार पर है. आगामी विधानसभा चुनावों में मुकाबला असली कांग्रेस और पुरानी

कांग्रेस के बीच होगा. उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी पुराने कांग्रेस नेताओं से भरी पड़ी है, जो राज्य में कांग्रेस के 15 साल के शासनकाल में सबसे भ्रष्ट थे. असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की ओर से बोरा को कांग्रेस का आखिरी हिंदू नेता कहने पर गोगोई ने आरोप लगाया कि वह (हिमंता बिस्वा सरमा) असम के जिन्ना हैं और उन्हें नेताओं को हिंदू प्रमाण पत्र देना बंद कर देना चाहिए. कांग्रेस एक समंदर की तरह है और हम सब उसमें पानी की बूंदें मात्र हैं. कांग्रेस हमारे पूर्वजों के अस्तित्व से बहुत पहले से मौजूद है.

राहुल गांधी पर भड़के भूपेन बोरा

भूपेन बोरा ने बुधवार को दावा किया कि असम कांग्रेस अब गौरव गोगोई के नियंत्रण में नहीं है, बल्कि धुबरी के सांसद रकीबुल हुसैन पार्टी के मुख्य कर्ताधर्ता हैं. बोरा ने कहा कि सोमवार को उनके द्वारा कांग्रेस आलाकमान को अपना त्यागपत्र भेजने के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उन्हें फोन किया. भूपेन बोरा ने दावा किया, 'उन्होंने (राहुल गांधी ने) इसका उल्लेख किया कि कैसे हमने मिलकर पार्टी को आगे बढ़ाया जो सच है, लेकिन उन्होंने मेरे त्यागपत्र के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा.'

कांग्रेस को मेरी जरूरत नहीं- भूपेन बोरा

उन्होंने कहा, मुझे एहसास हुआ कि पार्टी में मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया. कांग्रेस के राज्य प्रभारी जितेंद्र सिंह ने नौ फरवरी को पार्टी के छह नेताओं के साथ एक बैठक की थी और उन्हें विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन की बातचीत आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई थी. मैंने यह स्वीकार किया क्योंकि यह पार्टी का निर्णय था और मुझे यह भी लगा कि गठबंधन आवश्यक है क्योंकि कांग्रेस अकेले बीजेपी का सामना नहीं कर सकती.

मायावती ने यूपी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का किया एलान

लखनऊ । राजधानी लखनऊ में बुधवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने अकेले यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने का एलान किया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि इन दिनों लोकतंत्र एवं संविधान को मजबूती प्रदान करने के बजाय आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस को सफलता की कुंजी बताने की स्वार्थी चर्चाएं चल रही हैं। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि यूपी में जैसे-जैसे चुनाव पास आएंगे, जो लोग हमारे खिलाफ हैं, वे हमें सत्ता से दूर रखने की और भी कोशिश करेंगे। हमारे खिलाफ साजिश करेंगे। सिर्फ यूपी में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में सभी अंबेडकरवादियों को बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर का आत्म-सम्मान पाने के आंदोलन को मजबूत करने के लिए काम करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि बसपा के यूपी विधानसभा चुनाव गठबंधन में लड़ने की बात फेक न्यूज है। यह बिल्कुल गलत, झूठ, हवा-हवाई व मनगढ़ंत है। बसपा अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। बसपा के लोगों को यह अच्छी तरह से मालूम है कि कांग्रेस, सपा व भाजपा आदि पार्टियों की सोच संकीर्ण व अंबेडकर विरोधी है। ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ही इस प्रकार की घिनौनी साजिशें करते रहते हैं। पार्टी समर्थक और कार्यकर्ता इनकी की मस्त चाल चलते रहें। 2007 की तरह ही अकेले चुनाव लड़कर फिर से बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं। बसपा सुप्रीमो ने दिल्ली के बंगले पर कहा कि मेरी सुरक्षा के हिसाब से लंबे समय बाद टाइप-8 बंगला अलाट हुआ है। इसे मैंने स्वीकार कर लिया है। लेकिन, कुछ लोग इसके बारे में भी गलत व गुमराह करने वाली बातें फैला रहे हैं। इससे भी लोगों को सावधान रहने की जरूरत है।

चलती ट्रेन में हैवानियत : युवती से दुष्कर्म मामले में आरोपी टीटीई निलंबित, 10 हजार का इनाम; तलाश में छापेमारी

गोरखपुर । गोरखपुर-अहमदाबाद एक्सप्रेस के एसी प्रथम श्रेणी कोच में युवती से दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया है। आरोपी टीटीई राहुल कुमार को रेलवे प्रशासन ने निलंबित कर दिया है। एसपी जीआरपी लक्ष्मी निवास मिश्रा ने आरोपी के खिलाफ 10 हजार रुपये इनाम घोषित किया है। जीआरपी की कई टीमें आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। आरोपी राहुल कुमार मूलरूप से बिहार के पटना का रहने वाला है और घटना के बाद से लापता है। मूलरूप से मऊ जिले की रहने वाली 22 वर्षीय युवती गोरखपुर में किराए पर कमरा लेकर सेना भर्ती की तैयारी कर रही है। रविवार को वह एनसीसी 'सी' सर्टिफिकेट की परीक्षा देकर लौट रही थी। बलिया स्टेशन पर हड़बड़ी में टिकट न ले पाने के कारण वह ट्रेन में सवार हो गई। आरोप है कि टीटीई ने बिना टिकट की कार्रवाई का डर दिखाते हुए पहले सीट दिलाने का भरोसा दिया और फिर एसी प्रथम श्रेणी कोच के केबिन में ले जाकर

इंदारा और देवरिया के बीच चलती ट्रेन में दुष्कर्म की कोशिश की। पीड़िता के अनुसार, विरोध करने पर आरोपी ने कार्रवाई की धमकी दी। किसी तरह केबिन से बाहर निकलकर उसने 112 नंबर पर फोन कर घटना की सूचना दी। इसके बाद राहुल कुमार देवरिया में ट्रेन से उतरकर भाग निकला। गोरखपुर पहुंचने पर युवती ने इसकी शिकायत जीआरपी थाने में की। मामले में युवती की तहरीर पर आरोपी टीटीई के खिलाफ दुष्कर्म की कोशिश समेत अन्य गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर देर रात विवेचना देवरिया ट्रांसफर कर दिया गया। उधर, घटना का संज्ञान लेते हुए रेलवे प्रशासन ने आरोपी टीटीई को निलंबित कर दिया है। जीआरपी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीमें पटना और अन्य संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।

बोले एसपी रेलवे

एसपी रेलवे लक्ष्मी निवास मिश्र ने कहा कि आरोपी की तलाश में जीआरपी स्थानीय पुलिस के साथ दबिश दे रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पीड़िता का मेडिकल व बयान देवरिया में होगा। परिवार के लोग भी पहुंच गए हैं।

महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान

नई दिल्ली । भारत के चुनाव आयोग ने राज्यसभा के लिए चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है. यह चुनाव उन सदस्यों की जगह भरने के लिए कराया जा रहा है, जिनका कार्यकाल अप्रैल 2026 में पूरा हो रहा है. कुल 10 राज्यों की 37 सीटों पर चुनाव होगा. चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 26 फरवरी 2026 को अधिसूचना जारी की जाएगी. नामांकन दाखिल करने, जांच और नाम वापस लेने की प्रक्रिया तय समय सीमा के अनुसार पूरी की जाएगी. इन सभी सीटों के लिए 16 मार्च 2026 को मतदान

होगा. मतदान उसी दिन होगा और मतगणना भी 16 मार्च को ही की जाएगी. यह चुनाव महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश की सीटों के लिए कराया जाएगा. राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और राज्यों में चुनावी हलचल तेज हो गई है. नोटिफिकेशन जारी होगा 26 फरवरी 2026 को. नामांकन की आखिरी तारीख 5 मार्च 2026 तय की गई है. नामांकन पत्रों की जांच 6 मार्च 2026 को होगी. नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 9 मार्च 2026 है. मतदान 16 मार्च 2026 को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा. मतगणना 16 मार्च 2026 को शाम 5 बजे से शुरू होगी. चुनाव प्रक्रिया 20 मार्च 2026 तक पूरी कर ली जाएगी.

आरएसएस भाजपा का रिमोट कंट्रोल नहीं है - मोहन भागवत

वेबवार्ता

लखनऊ । राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार को कहा कि संघ भाजपा का रिमोट कंट्रोल नहीं है। संघ के स्वयंसेवक भाजपा में जाते हैं। वहां आगे भी बढ़े हैं। लेकिन यह कहना गलत है कि संघ भाजपा को चलाता है। हालांकि, भाजपा का विरोध करने वाले लोग ही संघ का विरोध करते हैं। मोहन भागवत ने अमेरिकी टैरिफ पर कहा- यह उनका पुराना तरीका है। वे हथियार और आर्थिक ताकत के दम पर झुकाना चाहते हैं। लेकिन भारत इतना मजबूत है कि उनके आगे झुका नहीं है। हमारी जनता तैयार है। इसलिए इसका भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। संघ प्रमुख ने मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने पर कहा, सवाल यह है कि मंदिरों की देखभाल कौन करेगा, वहां नियमित पूजा पाठ हो, इसकी चिंता कौन

अमेरिकी टैरिफ पर लखनऊ में कहा- वे ताकत के दम पर झुकाना चाहते हैं

करेगा। सिख समाज अपने गुरुद्वारे का संचालन बहुत अच्छा करता है। देश के धर्माचार्यों को इस पर मंथन करना चाहिए और समाज को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मोहन भागवत ने ये बातें लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कहीं। वे बुधवार सुबह लखनऊ विश्वविद्यालय पहुंचे थे। जहां उनके पहुंचते ही हंगामा शुरू हो गया था। NSUI, समाजवादी छात्र सभा और भीम आर्मी से जुड़े छात्रों ने 'गो बैक मोहन भागवत' के नारे लगाए।

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया।

मोहन भागवत के भाषण की 8 बड़ी बातें

1. यूजीसी मामला कोर्ट में है- यूजीसी से जुड़ा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। कोर्ट जो फैसला देगा, उसी के अनुसार आगे देखा जाएगा। कानून गलत हो तो उसे बदलने का तरीका भी है।

2. हम सब एक हैं, छुआछूत खत्म होनी चाहिए- हम सब भारत माता के बेटे-बेटी हैं। रंग, रूप या जाति अलग हो सकती है, लेकिन अपनापन बना रहना चाहिए। यही भावना छुआछूत जैसी बुराई खत्म कर सकती है।

3. जाति व्यवस्था अब पुरानी हो चुकी है- जाति नाम की कोई व्यवस्था अब रहनी नहीं चाहिए। पहले यह काम के आधार पर थी, अब समय बदल गया है। जाति की दीवारें धीरे-धीरे टूट रही हैं।

4. हिंदू समाज बंटा हुआ है- हिंदू समाज में ताकत है, लेकिन वह बंटा हुआ है और स्वार्थ में फंसा है। अगर समाज एकजुट हो जाए तो देश को आगे बढ़ा सकता है।

5. आधुनिकीकरण ठीक, नकल सही नहीं- नई चीजों का विरोध नहीं है, लेकिन पश्चिमीकरण की नकल सही नहीं है। आधुनिक बनें, लेकिन अपनी जड़ों और संस्कृति को न भूलें।

6. परिवार और संस्कार जरूरी- संयुक्त परिवार अब कम हो गए हैं, लेकिन रिश्तों का भाव बना रहना चाहिए। हफ्ते में कम से कम एक बार परिवार साथ बैठे। बच्चों को संस्कार घर और स्कूल दोनों से मिलते हैं।

7. सोशल मीडिया का सही उपयोग करें- सोशल मीडिया तकनीक है। उसके मालिक बनें, गुलाम नहीं। स्क्रीन टाइम तय करें और बच्चों को सही दिशा दें।

8. समाज जागरूक होगा तो राजनीति सुधरेगी- राजनीति समाज से बनती है। अगर समाज में सद्भाव और समझदारी होगी तो नेता भी वैसे ही होंगे। समाज जागरूक होगा तो हालात सुधरेंगे।

लखनऊ यूनिवर्सिटी में लगे भागवत गो बैक के नारे

लखनऊ विश्वविद्यालय में बुधवार सुबह संघ प्रमुख मोहन भागवत के पहुंचते ही हंगामा शुरू हो गया। NSUI, समाजवादी छात्र सभा और भीम आर्मी से जुड़े छात्र 'गो बैक मोहन भागवत' के नारे लगाने लगे। पुलिस ने जब छात्रों को रोकने की कोशिश की, तो नोकझोंक और खींचतान शुरू हो गई। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को ठूंस-ठूंसकर जीप और बसों में भरा। कई छात्र लेट गए, तो उन्हें टांगकर ले जाया गया। सभी छात्रों को इको गार्डन भेजा गया। इसके बाद मोहन भागवत का कार्यक्रम हुआ। भागवत ने कहा- धूल का एक कण भी धर्म से अलग नहीं हो सकता।

NSUI कार्यकर्ता शुभम यादव ने कहा-

संघ से जुड़े लोगों को विश्वविद्यालय में कार्यक्रम करने की अनुमति दी जा रही है, जबकि विपक्षी छात्र संगठनों को हॉल तक नहीं मिलते। यूजीसी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है। इसके बावजूद आरएसएस प्रमुख की ओर से कोई बयान नहीं आया है। भागवत दो दिवसीय लखनऊ प्रवास पर हैं। आज लखनऊ यूनिवर्सिटी में संगोष्ठी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम में भाग लेंगे।